भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2284

16 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रमुख शहरों में शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव

2284. श्री एस निरंजन रेड्डी:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव के कारण केवल शहरीकरण के फलस्वरूप तापमान में 60 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय शहरों में बढ़ते तापमान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क (सीएससीएएफ) को लागू किया है;

(ग) इस फ्रेमवर्क के तहत आकलन के अनुसार कौन से विशिष्ट शहरों में सबसे अधिक तापमान वृद्धि देखी गई है; और

(घ) शहरों में शहरी तापमान प्रवृत्तियों तथा जलवायु प्रतिरोधक्षमता की निगरानी करने के लिए क्या निगरानी तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): शहरीकरण से भारतीय शहरों में कम वनस्पति, तापमान अवशोषी निर्माण सामग्री और ऊर्जा की बढ़ती मांगों के कारण तापमान में काफी बढ़ोत्तरी होती है। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन और विकास शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/ शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। शहरी उष्मा द्वीप प्रभाव से निपटने के

लिए, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत 5,044.28 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,429 पार्क परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिससे 5,044 एकड़ हरित स्थान विकसित किया जा चुका है। अमृत 2.0 के तहत अब तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा 1,027.62 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,729 पार्क परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अमृत 2.0 के तहत अब तक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 6,159.29 करोड़ रुपये की लागत वाली 3,078 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों को परामर्शिका के रूप में "भारत शीतलन कार्य योजना 2019" पर आदर्श भवन निर्माण उपनियम (एमबीबीएल)-2016 का परिशिष्ट जारी किया है।
  https://www.mohua.gov.in/upload/whatsnew/61b9785b508c3mbbl2016.pdf

- इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में शहरी हरित दिशानिर्देश, 2014 जारी किए गए हैं।
  https://www.mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/G%20G%202014(2).pdf
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अध्याय 5 - शहरी नियोजन दृष्टिकोण के माध्यम से जारी शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निरूपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशा-निर्देश खुले स्थानों/हरित स्थानों और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए अधिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए कॉम्पैक्ट और ग्रीन सिटी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने का समर्थन करते हैं, जिससे शहरी अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्र कम बनेंगे।
  mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI दिशानिर्देश खंड I(2).pdf

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद 2019 में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क (सीएससीएएफ) शुरू किया। सीएससीएएफ में शहर की जलवायु परिवर्तन के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया का व्यापक मूल्यांकन दिया गया है, जिसमें ऊर्जा दक्षता, जल प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित क्षेत्र और जलवायु अनुकूलन कार्यनीतियों जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सीएससीएएफ आकलन आकड़ों (https://niua.in/cscaf) पर आधारित शहरों की रेडीनेस रिपोर्ट 3.0 के अनुसार

- 95 शहरों ने एनडीएमए दिशानिर्देश के आधार पर वार्ड स्तर पर जोखिम, असुरक्षा और क्षमता आकलन सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार की है।
- 85 शहर अपनी नगरपालिका सीमाओं के भीतर 12% से अधिक हरित आवरण के निर्धारित यूआरडीपीएफआई मानदंड को पूरा कर रहे हैं।
- 76 शहरों को जलाशय और खुले क्षेत्रों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए बजट आवंटित किया गया है।
- 41 शहरों ने दर्शाया है कि उन्होंने या तो अपनी जलवायु कार्य योजना विकसित कर ली है या विकसित कर रहे हैं।

भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) के राष्ट्रीय संचार (नैटकॉम) प्रकोष्ठ ने सूचित किया है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की आकलन रिपोर्ट 6 (एआर6) की 'विश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023' के अनुसार, मानवीय गतिविधियां, मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के माध्यम से, स्पष्ट रूप से ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनी है, जिससे 2011-2020 में वैश्विक सतह का तापमान 1850-1900 की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है।

नैटकॉम प्रकोष्ठ ने आगे सूचित किया है कि 2023 में जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत किए गए तीसरे राष्ट्रीय संचार (टीएनसी) के अनुसार, 1901-2022 के दौरान देश का औसत वार्षिक तापमान 0.64° सेल्सियस/100 वर्षों की वृद्धि प्रवृत्ति को दर्शाता है।

*****